संख्या-92/2021/1037/23-10-21-60(सेतु)/2014

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्य ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 18 अक्टूबर, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57 एवं अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद बिजनौर में नजीबाबाद बालावली लक्सर मार्ग पर बालावली के निकट गंगा नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-405/पुन0आगणन-बिजनौर (बालावली-लक्सर)/सेतु-6/2020 दिनांक 06.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद बिजनौर में नजीबाबाद बालावली लक्सर मार्ग पर बालावली के निकट गंगा नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है । उक्त सेतु की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-15/2015/358/23-10-15-60(सेतु)/2014, दि0 23.02.2015 द्वारा लागत रू0 3995.66 लाख की राज्य योजना के अंतर्गत प्रदान की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, निम्नांकित विवरणानुसार लागत रू0 6199.20 लाख (रूपये इकसठ करोड़ निन्यानबें लाख बीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान की जाती हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमसं0	जनपद/कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत /पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4
1-	जनपद बिजनौर में नजीबाबाद बालावली लक्सर मार्ग पर बालावली के निकट गंगा नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	3995.66	6199.20
	योग-	3995.66	6199.20

(1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय ।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7) परियोजनान्तर्गत जुलाई, 2017 से कराये गये कार्यों पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्र्तगत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो ।

(8) प्रायोजनान्तर्गत वन विभाग (पेड़ो की कटाई एवं वृक्षारोपण) द्वारा रू0 1.31 लाख की लागत का प्रस्ताव है, जिसे यथावत अनुमन्य कर दिया गया है। निर्माण के समय वास्तविक भुगतान/व्यय के अनुसार धनराशि देय होना विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

(9) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति(0.738हे0) की लागत य0 141.24 लाख एवं भवनों का मुआवजा (04 नग) 32.108 व0मी0 की लागत रू0 1.08 लाख प्रस्तावित की गयी है। भूमि अध्याप्ति एवं मुआवजा न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा ।

(10) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) प्रश्नगत परियोजना की मूल स्वीकृत विषयक शासनादेश की शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(13) प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनावंटन की कार्यवाही विभागाध्यक्ष से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरांत की जायेगी ।

(14) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः

http://shasanadesh.up.nic.in

(15) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021-बी-1-375/दस-2021-231/ 2021 दिनॉक 22 मार्च 2021 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा । वित्त नियंत्रक द्वारा कार्यदायी संस्था को 02-02 माह की आवश्कतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिये उन्हें आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी ।

(16) भारत सरकार की कोविड-19 हेतु जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

(17) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-04-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0421-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-14-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8- 1418 /दस-2021, दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
उप सचिव।

<u>संख्या-92/2021/1037(1)/23-10-21,तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) मण्डलायुक्त, मुरादाबाद / जिलाधिकारी, बिजनौर ।
(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
(4) मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियंता, मुरादाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in